साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 03 में...
आंबेडकर अस्पताल: जहां तकनीक 'वेंटिलेटर' पर है!

गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं

गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर दिनांक 26 जनवरी (सोमवार) को शहरसत्ता कार्यालय में अवकाश रहेगा जिसके कारण अगला प्रकाशन 2 फरवरी (सोमवार) को होगा। हम अपने समस्त सम्मानित पाठकों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

वर्ष : 01 अंक : 46 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com
पेज 04 धर्मांतरण पर आर-पार की जंग

रायपुर DEO ऑफिस अग्निकांड

हादसा या षड़यंत्र !

करोड़ों के रिकॉर्ड स्वाहा, संदेह के घेरे में विभाग

शहर सत्ता/रायपुर

राजधानी के पेंशन बाड़ा स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्टोर रूम में शनिवार शाम लगी भीषण आग ने विभाग के "तिजोरी" माने जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें जितनी ऊंची थीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा इस घटना के पीछे का रहस्य नजर आ रहा है। यह आग केवल कागजों की राख नहीं है, बल्कि उन हजारों शिकायतों, जांचों और रिकॉर्ड्स का अंत है जो विभाग के भीतर चल रही सच्चाई को उजागर कर सकते थे। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह आग वाकई बिजली के तारों की 'चिंगारी' से लगी या फिर किसी ने 'माचिस' लगाकर सालों पुराने पापों को धो डालने की कोशिश की है?

छुट्टी का दिन और स्टोर रूम का ही चयन क्यों?

शनिवार शासकीय छुट्टी, जब कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति नही थी, अचानक स्टोर रूम से धुआं उठने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग ने इतनी तेजी से विकराल रूप धारण किया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की, लेकिन जब तक आग बुझी, तब तक विभाग की 'याददाश्त' (रिकॉर्ड रूम) खाक हो चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग कार्यालय के मुख्य हिस्से, कंप्यूटर रूम या साहब के केबिन में क्यों नहीं लगी? आग सिर्फ उस स्टोर रूम में ही क्यों भड़की, जहां दशकों पुराने और वर्तमान में चल रही जांचों के सबसे संवेदनशील दस्तावेज रखे थे? क्या यह महज इत्तेफाक है या एक सुनियोजित 'टाइमिंग' का हिस्सा?

राख में तब्दील हुए ये महत्वपूर्ण दस्तावेज, आखिर किसका होगा फायदा?

शिक्षा विभाग में आग लगने का मतलब है हजारों छात्रों, शिक्षकों और योजनाओं के भविष्य पर संकट, जो फाइलें जलकर खाक हुई हैं, उनमें से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे

स्कूलों की मान्यता का 'खेल'

रायपुर जिले के सैकड़ों निजी स्कूलों को नियमों को ताक पर रखकर दी गई मान्यता से जुड़ी फाइलें इस स्टोर रूम में थीं। कई स्कूलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा मानकों को पूरा न करने के बावजूद मान्यता देने के आरोप थे, जिनकी जांच चल रही थी। अब सबूत ही नहीं बचे।

मध्यान्ह भोजन (MDM) घोटाला

स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के नाम पर करोड़ों रुपये के फर्जी बिल भुगतान और सामग्री आपूर्ति की शिकायतें लंबे समय से लंबित थीं। स्टोर रूम में इन भुगतानों के मूल वाउचर और स्टॉक रजिस्टर रखे थे।

अनुकंपा नियुक्ति में अनियमितता

पिछले कुछ वर्षों में अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर अपात्र लोगों को लाभ देने की शिकायतें सामने आई थीं। इससे संबंधित वरिष्ठता सूची और आपत्ति वाली फाइलें अब राख का ढेर बन चुकी हैं।

विभागीय जांच (DE) के साक्ष्य

विभाग के उन अधिकारियों और बाबूओं के खिलाफ चल रही जांच के दस्तावेज, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। साक्ष्यों के अभाव में अब इन दोषियों को बचाना आसान हो जाएगा।

शिकायत निवारण फाइलें

आम जनता और शिक्षकों द्वारा विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई दर्जनों लिखित शिकायतें, जिन पर कार्रवाई प्रस्तावित थी।

साप्ताहिक शहर सत्ता

'शॉर्ट सर्किट' बना सबसे आसान बहाना

हर सरकारी कार्यालय में जब भी आग लगती है, तो प्रारंभिक जांच में 'शॉर्ट सर्किट' का नाम लेकर फाइल बंद कर दी जाती है। लेकिन रायपुर DEO ऑफिस के मामले में जनता और विपक्ष दोनों इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

शंका के तीन मुख्य आधार

1 ऑडिट का समय

बताया जा रहा है कि आगामी महीनों में विभाग का बड़ा ऑडिट होना था। ऑडिट से पहले फाइलों का गायब होना या जलना भ्रष्टाचार की पुरानी स्क्रिप्ट रही है।

2 डिजिटलीकरण की सुस्ती

जब शासन हर फाइल को डिजिटल करने पर जोर दे रहा है, तो इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों का बैकअप क्यों नहीं रखा गया? क्या इसलिए कि डिजिटल रिकॉर्ड को जलाया नहीं जा सकता?

3 फायर सेफ्टी का अभाव

राजधानी के केंद्र में स्थित इतने बड़े कार्यालय में फायर अलार्म और आग बुझाने के यंत्रों का काम न करना यह दर्शाता है कि शायद लापरवाही जानबूझकर बरती गई।

प्रशासनिक हड़कंप और 'लीपापोती' की आशंका

घटना के बाद से शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों में हड़कंप है। आनन-फानन में नुकसान का आकलन करने के लिए एक टीम बनाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो अधिकारी खुद विभाग का हिस्सा हैं, वे अपनी ही नाक के नीचे हुई इस संदिग्ध घटना की निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे? शहर के जागरूक नागरिकों और आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह आग उन फाइलों को दबाने के लिए लगाई गई है जो बड़े अफसरों और राजनेताओं के गठजोड़ को बेनकाब कर सकती थीं। यदि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने स्टोर रूम के मलबे से पेट्रोल या किसी अन्य ज्वलनशील पदार्थ के निशान पाए, तो यह प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक षड्यंत्र साबित हो सकता है।

भविष्य की चुनौतियां: अब क्या होगा?

दस्तावेजों के जलने से सबसे अधिक परेशानी उन आम शिक्षकों और कर्मचारियों को होगी जिनकी पेंशन, पदोन्नति या वेतन विसंगति के मामले इन फाइलों के भरोसे टिके थे। अब उन्हें अपनी बेगुनाही या पात्रता साबित करने के लिए सालों भटकना पड़ेगा। वहीं, भ्रष्टाचार के आरोपियों के लिए यह आग एक 'वरदान' साबित होगी, क्योंकि अब उनके खिलाफ कोई ठोस दस्तावेजी सबूत नहीं बचा है।

आग की जांच के लिए बनी एसआईटी

विभागीय भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं और राजनेताओं का कहना है कि DEO ऑफिस की यह आग महज एक विभागीय क्षति नहीं, बल्कि पारदर्शिता पर हमला है। इसकी जांच केवल पुलिस या शिक्षा विभाग के स्तर पर न होकर, किसी सेवानिवृत्त जज या एसआईटी (SIT) द्वारा की जानी चाहिए। साथ ही, यह भी देखा जाना चाहिए कि आग लगने के दौरान सीसीटीवी कैमरे चालू थे या उन्हें भी साजिश के तहत बंद कर दिया गया था। यह आग बुझ चुकी है, लेकिन इसने जो सवाल खड़े किए हैं, उनकी तपिश लंबे समय तक विभाग को झुलसाती रहेगी। राजधानी के दिल में हुई इस घटना ने साफ कर दिया है कि अगर रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं हैं, तो न्याय भी सुरक्षित नहीं है।

तीन लोगों की टीम बताइगी आग लगी या लगाई गई

DEO कार्यालय में लगी भीषण आग को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस मामले की गहन जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जो आग लगने के कारणों और इससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। संभागीय संयुक्त संचालक संजय श्रीवास्तव को इस जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सहायक संचालक बजरंग प्रजापति और सतीश नायर समिति के सदस्य होंगे। समिति को 5 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

आंबेडकर अस्पताल: जहां तकनीक 'वेंटिलेटर' पर है!

2005 की मशीनों से 2026 का इलाज, बजट की फाइलों में दफन हुआ मरीजों का हक

रायपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा), आज खुद एक 'लाचार मरीज' की तरह नजर आ रहा है। विडंबना देखिए कि जिस अस्पताल पर पूरे प्रदेश के मरीजों को जीवनदान देने की जिम्मेदारी है, वहां का तकनीकी ढांचा खुद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। चिकित्सा विज्ञान जहां आज रोबोटिक सर्जरी और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के दौर में पहुंच गया है, वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी का यह 'लाइफलाइन' अस्पताल 2005 और 2006 की 'जंग खाई' मशीनों के भरोसे चल रहा है।

तकनीकी 'पाषाण युग' में जी रहा रेडियोलॉजी विभाग

आंबेडकर अस्पताल के भीतर का मंजर किसी म्यूजियम जैसा प्रतीत होता है। अस्पताल के रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभाग, जो किसी भी गंभीर बीमारी की पहचान (डायग्नोसिस) की नींव होते हैं, वहां मशीनें 18 से 20 साल पुरानी हैं।

- **सोनोग्राफी का 'धुंधला' सच:** अस्पताल में आज भी 2005 मॉडल की सोनोग्राफी मशीनों से जांच की जा रही है। 18-20 साल पुरानी इन मशीनों की रिपोर्ट कितनी सटीक होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद सरकारी डॉक्टर इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं।
- **एमआरआई और सीटी स्कैन की थकान:** 2012 में खरीदी गई ये मशीनें अब कबाड़ होने की कगार पर हैं। मरीजों का दबाव इतना अधिक है कि मशीनें बार-बार जवाब दे जाती हैं, जिससे जांच के लिए हफ्तों की वेटिंग मिल रही है।
- **दम तोड़ती एक्स-रे मशीनें:** अस्पताल की पांच में से एक मशीन पूरी तरह बंद हो चुकी है, जबकि बाकी मशीनें अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ झेल रही हैं।

जब रक्षक ही हो जाए बेबस डॉक्टरों का सिस्टम से मोहभंग

अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर इलाज तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 'हथियार' पुराने और कुंद हो चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि जिला अस्पताल (पंडरी) और आंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर खुद मरीजों को निजी सेंटरों पर जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। हाल ही में सामने आया सुबोध साहू का मामला इस कड़वे सच की तस्दीक करता है, जहां सरकारी रिपोर्ट में 'सब ठीक' होने के बावजूद डॉक्टर ने खुद निजी अस्पताल से अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। यह इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम को चलाने वाले हाथ अब खुद सिस्टम की विश्वसनीयता पर भरोसा खो चुके हैं।

बजट की 'सर्जरी', कागजों में फंसी नई मशीनें

- हैरानी की बात यह है कि समस्या फंड की कमी से ज्यादा प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी की लगती है।
- प्रस्ताव बनाम स्वीकृति: अस्पताल प्रबंधन ने कायाकल्प के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था।
- आधा अधूरा बजट: सरकार ने 94.5 करोड़ रुपये स्वीकृत भी किए।
- टेंडर का मकड़जाल: स्वीकृत राशि होने के बावजूद टेंडर की प्रक्रिया और लालफीताशाही (Red Tapism) के कारण नई मशीनें अब तक अस्पताल की दहलीज पार नहीं कर पाई हैं।

कैंसर मरीजों पर दोहरी मार

सबसे दुखद स्थिति कैंसर विभाग की है। 'लीनियर एक्सीलेरेटर' जैसी जीवन रक्षक मशीनों का आउटडेटेड होना मरीजों के लिए मौत के वारंट जैसा है। गरीब मरीज, जो निजी अस्पतालों का खर्च वहन नहीं कर सकते, वे इन पुरानी मशीनों से हो रहे 'अधूरी गुणवत्ता' वाले इलाज के बीच पिस रहे हैं।

सवाल जो जवाब मांगते हैं:

- क्या 20 साल पुरानी मशीनों से दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया इलाज सुरक्षित है?
- बजट स्वीकृत होने के बावजूद टेंडर प्रक्रिया में देरी का जिम्मेदार कौन है?
- क्या राजधानी के इस बड़े अस्पताल को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि निजी अस्पतालों की जेबें भरी जा सकें?

प्रबंधन का पक्ष

आंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर का कहना है कि एमआरआई और दो सीटी स्कैन मशीनों के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। शेष मशीनों के लिए अधिष्ठाता कार्यालय से प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

क्रिप्टो और शेयर बाजार के नाम पर 1.35 करोड़ का मायाजाल, सलाखों के पीछे 'फर्जी गुरु'

रायपुर। निवेश की दुनिया में जब लालच हावी होता है, तो डिग्रियां बौनी पड़ जाती हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ महज छठी तक पढ़े एक शख्स ने 'निवेश सलाहकार' का चोला ओढ़कर पढ़े-लिखे लोगों को सवा करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगा दिया। पंडरी पुलिस और साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने धमतरी रोड निवासी कुलदीप भतपहरी को गिरफ्तार किया है, जिसने शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी की बारीकियों का झूठा स्वांग रचकर 26 लोगों की जमापूंजी डकार ली। यह ठगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आरोपी कुलदीप ने खुद को एनएसई, सीडीएसएल और आईपीओ मार्केट का दिग्गज विशेषज्ञ बताकर 'केबी प्लान' नामक एक काल्पनिक स्कीम बाजार में उतारी। उसने लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफलता हासिल की कि उसके पास निवेश का ऐसा जादुई फॉर्मूला है जो हर महीने निश्चित ब्याज और भारी मुनाफा दिला सकता है। इस जाल में फंसे अमित दास और उनके भाई रोहित दास ने भरोसा करते हुए करीब 15 लाख रुपये से अधिक की राशि आरोपी को सौंप दी। ठगी की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने शुरुआत में कुछ लोगों को ब्याज की राशि लौटाई, ताकि बाजार में उसकी साख बनी रहे और बड़े शिकार उसके जाल में खुद-ब-खुद खिंचे चले आएं। पुलिस की तफ्तीश में जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला है। आरोपी कुलदीप कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी है जो पहले भी टिकरापारा थाने से ठगी के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। वर्ष 2025 में भी उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने फिर से अपना शिकार खोजना शुरू कर दिया।

छग से आ रही बस लातेहार में दुर्घटनाग्रस्त, 6 की मौत

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लोध फाल जा रही एक यात्री बस रविवार को ओरसा घाटी में भीषण हादसे का शिकार हो गई। बस का ब्रेक फेल हो जाने से वह अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में चार महिलाओं और दो पुरुषों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 70 से अधिक यात्री घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटनाग्रस्त बस ज्ञान गंगा हाई स्कूल, बलरामपुर की बताई जा रही है, जिसका पंजीयन संख्या सीजी-15 एबी 0564 है। सभी लोग छत्तीसगढ़ बलरामपुर के महाराजगंज गांव से सगाई कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। पुलिस और स्थानीय लोग राहत कार्य में लगे हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। ओरसा घाटी की तीखी ढलान पर पहुंचते ही बस अचानक तेज रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ने लगी और कुछ ही पलों में पलट गई। बस के पलटने से कई यात्री बस के नीचे दब गए। बस चालक विकास पाठक ने बताया कि घाटी में उतरते समय ही उन्हें ब्रेक फेल होने का एहसास हो गया था। उन्होंने बस को नियंत्रित करने के लिए हैंडब्रेक का भी सहारा लिया, लेकिन ढलान होने के कारण बस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका। चालक के मुताबिक उन्होंने यात्रियों को संभलने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही ग्राम ओरसा के दर्जनों महिला-पुरुष मौके पर पहुंचे और घायलों को बस के नीचे से बाहर निकालने में जुट गए।

धर्मांतरण पर आर-पार की जंग

19 सीटों का गणित और साय सरकार का नया 'हथौड़ा'

विशेष रिपोर्ट (रायपुर)

छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, जो दशकों तक नक्सलवाद के दंश से लहूलुहान रहा, आज बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। सरकार और सुरक्षा बलों की आक्रामक नीति के कारण नक्सलवाद अपने खात्मे के करीब है, लेकिन जैसे-जैसे जंगलों से गोलियों की गूंज शांत हो रही है, वहां 'धार्मिक ध्रुवीकरण' का एक नया और खतरनाक मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। यह संघर्ष अब केवल जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि रायपुर और दुर्ग जैसे विकसित शहरी इलाकों तक फैल चुका है। हमारी पड़ताल बताती है कि पिछले पांच वर्षों में राज्य के 19 जिलों में मतांतरण और प्रार्थना सभाओं को लेकर 200 से अधिक हिंसक बवाल हुए हैं, जिसने प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी है।

नक्सलवाद के बाद अब 'पहचान' की लड़ाई

बस्तर के जिन इलाकों में कभी माओवादियों की हुकूमत चलती थी, वहां अब 'आदिवासी बनाम धर्मांतरित आदिवासी' की जंग छिड़ गई है। सरकार नक्सलवाद को जड़ से मिटाने में सफल हो रही है, लेकिन इसी बीच स्थानीय स्तर पर समुदायों के बीच बढ़ता अविश्वास नई चुनौती बन गया है।

अकेले कांकेर और नारायणपुर जैसे जिलों में पिछले एक साल में दर्जनों ऐसी घटनाएं हुईं, जहां मूल आदिवासियों और ईसाई धर्म अपनाने वाले ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। टकराव का सबसे बड़ा केंद्र 'अंतिम संस्कार' की जमीन बन गई है। बस्तर के हॉटस्पॉट इलाकों में अब यह नियम कड़ाई से लागू किया जा रहा है कि जो व्यक्ति ईसाई बन चुका है, उसे गांव की पारंपरिक जमीन पर दफनाने नहीं दिया जाएगा। दिसंबर 2025 में कांकेर के आमाबेड़ा में हुई हिंसा इसी का चरम रूप थी, जहां चर्च में आगजनी हुई और एएसपी समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हुए।

चंगाई सभाएं: शहरी क्षेत्रों में तनाव का केंद्र

- **मैदानी इलाकों (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा)** में संघर्ष का पैटर्न थोड़ा अलग है। यहां चर्चों से ज्यादा निजी मकानों और अस्थाई पंडालों में होने वाली 'चंगाई सभाएं' विवाद की जड़ हैं।
- **कुकुरबेड़ा और मितान विहार (रायपुर):** इन इलाकों में 'बीमारी ठीक करने' के दावों के बीच जब हिंदू संगठनों ने हस्तक्षेप किया, तो स्थिति मारपीट तक पहुंच गई।
- **दुर्ग-भिलाई:** यहां औद्योगिक क्षेत्रों की बस्तियों में प्रार्थना सभाओं को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रलोभन देकर मतांतरित किया जा रहा है।

नई सरकार का सख्त रुख 'धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2024'

नक्सलवाद पर विजय पाने के बाद अब साय सरकार इस सामाजिक अस्थिरता को रोकने के लिए कमर कस चुकी है। सरकार ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है जो मतांतरण को लगभग असंभव बना देगा:

- **60 दिन का अल्टीमेटम:** अब किसी भी धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को शपथ पत्र देना होगा।
- **कठोर दंड:** जबरन या प्रलोभन देकर कराए गए मतांतरण पर अब 5 से 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रस्ताव है।
- **दोहरा सत्यापन:** परिवर्तन के बाद व्यक्ति को दोबारा प्रशासन के सामने पेश होकर यह पुष्ट करना होगा कि वह किसी दबाव में नहीं है।

सियासत और सुरक्षा: 19 सीटों का गणित

इस पूरे मामले में राजनीति भी गहराई से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 19 सीटें ऐसी हैं जहां ईसाई मतदाताओं की संख्या हार-जीत तय करती है। जशपुर और सरगुजा संभाग में यह प्रभाव सबसे ज्यादा है। प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि वह एक तरफ नक्सलवाद के खात्मे के बाद शांति बहाली करें और दूसरी तरफ इन मजहबी टकरावों को सामाजिक दंगों में बदलने से रोकें। वरिष्ठ जानकारों का मानना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते 'मतांतरण' की शिकायतों पर पारदर्शी कार्रवाई नहीं की, तो सुरक्षा बलों के लिए बस्तर में नक्सलवाद के बाद यह 'इंटरनल सिक्योरिटी' का सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा।

मतांतरण का 'ग्रे एरिया' कानून और पहचान का पेच

छत्तीसगढ़ में विवाद का सबसे बड़ा कारण 'कानूनी धर्मांतरण' और 'अनौपचारिक मतांतरण' के बीच का अंतर है।

- **कागजी हिंदू, आचरण ईसाई:** हिंदू संगठनों का दावा है कि बड़ी संख्या में लोग अपना सरनेम और जाति नहीं बदलते ताकि वे सरकारी आरक्षण और सुविधाओं का लाभ लेते रहें, लेकिन वे पूरी तरह ईसाई रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। इसे 'गुप्त मतांतरण' कहा जा रहा है।
- **कानून की सुस्ती:** छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 1968 का पुराना कानून प्रभावी है, जिसमें सजा के प्रावधान बेहद नरम हैं। इसी का फायदा उठाकर कई मिशनरी संस्थाएं 'सेवा' की आड़ में धर्म परिवर्तन के खेल को अंजाम दे रही हैं।

वर्ष 2025 की 10 बड़ी घटनाएं: जब मजहबी टकराव से दहला छत्तीसगढ़

1. कांकेर (दिसंबर 2025): बड़े तेवड़ा गांव में एक मतांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर आदिवासी और ईसाई समुदाय में खूनी संघर्ष हुआ। भीड़ ने चर्च और सरपंच के घर में आग लगा दी। इस हिंसा में एएसपी आशीष बंछोर सहित 20 पुलिसकर्मी घायल हुए।

2. रायपुर (अगस्त 2025): सरस्वती नगर के कुकुर बेड़ा में एक निजी मकान में चल रही प्रार्थना सभा को हिंदू संगठनों ने घेर लिया। मारपीट के बाद पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया।

3. दुर्ग-भिलाई (जुलाई 2025): कैलाश नगर में कथित धर्मांतरण के विरोध में बजरंग दल ने बड़ा प्रदर्शन किया। तनाव इतना बढ़ा कि पुलिस को चर्च के भीतर से 150 लोगों को बस में भरकर सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा।

4. रायपुर (अक्टूबर 2025): राजेंद्र नगर के परशुराम नगर में एक महिला का बीमारी ठीक करने के बहाने ब्रेनवॉश करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया।

5. बिलासपुर (जुलाई 2025): बंधवापारा के जोगी आवास में दो महिलाओं द्वारा संचालित प्रार्थना सभा में जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने अवैध चर्च पर कार्रवाई की।

6. कोरबा (दिसंबर 2025): सुतर्रा गांव के एक खेत में पंडाल लगाकर चल रही सभा पर ग्रामीणों ने हमला किया। सरपंच की शिकायत पर पास्टर बजरंग जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

7. बिलासपुर (अगस्त 2025): सकरी थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने एक चर्च जैसे ढांचे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इससे पहले पुलिस ने हिंदू संगठन की शिकायत पर पास्टर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया था।

8. रायपुर (जनवरी 2025): पंडरी के मितान विहार में एक 'चंगाई सभा' के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के अपमान का आरोप लगा। हंगामे के बाद पुलिस ने पादरी कीर्ति केशरवानी सहित तीन लोगों को जेल भेजा।

9. बालोद (दिसंबर 2025): परसदा गांव में एक धर्मांतरित बुजुर्ग के अंतिम संस्कार को लेकर 4 घंटे तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चला। हिंदू संगठनों के विरोध के चलते शव को सार्वजनिक श्मशान के बजाय निजी जमीन पर दफनाना पड़ा।

10. कोरबा (नवंबर 2025): रूमगड़ा की शांति नगर बस्ती में मतांतरण को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। सड़क जाम और लात-घूंसे चलने के बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

मौत के बाद भी नहीं मिला चैन, मतांतरित महिला के शव को गांव में दफनाने पर भारी बवाल

धमतरी/रायपुर। धमतरी जिले के ग्राम नवागांव-कंडेल में एक मतांतरित बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार को लेकर उपजा विवाद छत्तीसगढ़ में गहराते सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण की नई मिसाल बन गया है। शनिवार को 85 वर्षीय जोरबाई साहू के निधन के बाद जब परिजन उन्हें ईसाई रीति-रिवाज से गांव में ही दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तब स्थानीय ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने इसका तीखा विरोध शुरू कर दिया।

ग्रामीणों का स्पष्ट तर्क था कि मतांतरण के बाद वे अपनी मूल संस्कृति खो चुके लोगों को गांव की पारंपरिक सीमा के भीतर दफनाने की अनुमति नहीं देंगे। अर्जुनी थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की घंटों की मध्यस्थता के बावजूद जब ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे और तनाव हिंसक रूप लेने लगा, तब प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए शव को गांव से बाहर ले जाने का निर्णय लिया। अंततः मृतका के परिजनों को शव धमतरी शहर लाना पड़ा, जहां ईसाई कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। यह घटना बताती है कि प्रदेश में अब केवल जीवित लोगों के बीच ही नहीं, बल्कि मृत्यु के पश्चात 'अंतिम विश्राम' की जमीन को लेकर भी समुदायों के बीच अविश्वास की खाई कितनी गहरी हो चुकी है।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

बपौतीवाद की विदाई

यूं कहने को तो भारत में लोकतंत्र है, लेकिन इसका अंदरूनी मिजाज अब भी राजशाही वाला ही है। यानी सत्ता भले राजवंशों के हाथ से निकल कर लोकतंत्र के जरिए दलीय नेताओं के हाथों में आ गई लेकिन इन नेताओं ने कालांतर में अपना-अपना सियासी वंश खड़ा करके अप्रत्यक्ष रूप से देश में लोकतांत्रिक राजशाही ही स्थापित कर रखी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अमुमन हर राज्य में किसी ना किसी सियासी राजवंश का दबदबा नजर आ जाएगा। केंद्र में ये सिलसिला नेहरू के बाद गांधी सरनेम के साथ जारी है तो राज्यों में भी अपना-अपना सियासी कुनबा है। लेकिन महाराष्ट्र में हालिया हुए नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों ने भारतीय लोकतंत्र से सियासी वंशवाद या ठेठ शब्दों में कहें तो राजनीति से 'बपौतीवाद' की विदाई के संकेत दे दिए हैं।

वंशवाद के खिलाफ चलाई गई भाजपा की मुहिम का असर अब दिखाई देने लगा है। बिहार से लालू प्रसाद यादव के विरासत को मिली करारी हार के बाद सामने आए महाराष्ट्र के नगरीय निकाय नतीजे में भविष्य की राजनीति के गहरे संकेत छिपे हैं। इस संकेत में संदेश और सबक दोनों निहित हैं। महाराष्ट्र में भाजपा ने साम-दाम-दंड-भेद के जरिए दो-दो सियासी कुनबों को धूल चटाई है। इनमें से एक कुनबा ठाकरे ब्रदर्स का रहा जबकि दूसरा पवार का। बिहार के बाद महाराष्ट्र से वंशवादी राजनीति के सफाए के उपरांत भाजपा के टारगेट में वे राज्य हैं जहां सियासत को जागीर की तरह चलाने का चलन है। इनमें से फिलहाल उसका फोकस तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल पर है जहां इस साल चुनाव होने हैं।

महाराष्ट्र के नतीजों ने 'राजनीतिक जागीरदारों' को ये साफ संदेश दे दिया है कि राजनीति में बपौतीवाद के दिन अब चला-चली की बेला में है। राजनीतिक उत्तराधिकारियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि महज विरासत के बलबूते जनता को बरगला पाना अब आसान नहीं है। सियासी विरासत को महज भावनात्मक आधार पर आगे बढ़ा पाना उत्तराधिकारियों के कौशल पर निर्भर करता है और महाराष्ट्र के नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभाल पाने में उनके उत्तराधिकारी सिरे से नाकाम रहे हैं। कहां बाला साहेब ठाकरे का गर्वित हिंदुत्व और कहां उनके वारिसों की हिंदुत्वविमुख लिजलिजी विचारधारा। इस विचारात्मक विरोधाभास का नतीजा भाजपा की आशातीत सफलता के रूप में सबके सामने हैं।

ये बात आइने की तरफ साफ है कि जनता का अब परिवारवादी पार्टियों से मोहभंग हो चला है। जनता ये बात जान चुकी है कि जिन सियासी दिग्गजों ने अपने संघर्ष और कथित विचारधारा के बलबूते अपना वैचारिक आधार बनाया था, उसे संभाल पाने में उनके वारिस सर्वथा नाकाम साबित हो रहे हैं। अब केवल अपने राजनीतिक पूर्वजों के अतीत और कृतित्व का यशोगान करके सियासत नहीं चलाई जा सकती। ये बात कांग्रेस समेत दूसरे क्षेत्रीय दलों के झंडाबरदारों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है। वरना कभी ईवीएम, कभी वोटर लिस्ट तो कभी चुनाव आयोग पर तोहमत मढ़कर अपनी नाकामी को जस्टीफाई करने का विकल्प तो खुला ही है।

अयोध्या से सोमनाथ तक, भारत के स्वाभिमान का अधूरा चक्र हुआ पूरा

सुधांशु त्रिवेदी

भारत जनसंख्या में सबसे बड़ा, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, Digital Transaction में सबसे आगे और अनेक पैमानों पर शानदार प्रदर्शन करता हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अब यह प्रश्न है कि यह किन मूल्यों के आधार पर विकसित होगा। ध्यान रहे, भारत सिर्फ आधुनिक विश्व की उभरती शक्ति नहीं बल्कि विश्व की एक मात्र जीवंत प्राचीन सभ्यता है। इसका यह स्वरूप इसकी दुर्धर्ष जीवनी शक्ति से बचा है। अनेक बर्बर आक्रमणों के बाद भी अद्भुत संघर्ष करते हुए इसने अपने को अनादिकाल से जीवित रखा है।

संविधान निर्माताओं में मतभेद

स्वतंत्रता के समय यह प्रश्न महत्वपूर्ण था कि स्वतंत्रता की यात्रा सांस्कृतिक गौरव, स्वाभिमान की दिशा में आगे बढ़ेगी या गुलामी की ग्लानि के बोझ में दबी रहेगी। इस पर हमारे संविधान निर्माताओं में मतभेद था। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार उसका मुख्य बिंदु था। जहां सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी जैसे लोग सोमनाथ के पुनरुद्धार के पक्ष में थे वहीं पंडित नेहरू इसके विरुद्ध थे। पंडित नेहरू को लगता था कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान secularism के लिए खतरा होगा।

सरदार पटेल का मत

इसके विपरीत सरदार पटेल का मानना था कि इतिहास के हर आक्रमण के बाद सोमनाथ दोबारा खड़ा हुआ है तो स्वतंत्र भारत में इसे पूरे वैभव, गौरव के साथ पुर्नस्थापित होना चाहिए। के.एम. मुंशी का मानना था कि ऐसी स्वतंत्रता का क्या अर्थ जो हमसे गीता छीन ले और मंदिरों का सम्मान करने से रोके (पुस्तक Pilgrimage to freedom)। आश्चर्य की बात यह है कि सोमनाथ के पुनरुद्धार पर secular विरोध मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत सरकारी खर्चे पर नेहरू की सरकार के द्वारा किए जाने पर आड़े नहीं आ रहा था जिसका उल्लेख वी.एन. गाडगिल ने अपनी पुस्तक Government from within में किया है।

धार्मिक उन्माद पर नकाब

यह विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं था, सैद्धांतिक भी था। नेहरू ने अपनी पुस्तक Discovery of India में महमूद गजनी को एक योद्धा और पैसे की चाह में भारत पर आक्रमण करने वाला बताकर उसके धार्मिक उन्माद पर सेकुलर नकाब डालने का काम किया जबकि मध्ययुगीन लेखक फरिश्ता ने अपनी किताब तारीख-ए-फरिश्ता (अंग्रेजी अनुवाद जॉन ब्रिक्स, पेज-43, 44) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गजनी लाखों स्वर्ण मुद्राएं मिलने के प्रस्ताव के बाद भी मूर्ति तोड़ना ही चाहता था ताकि वह एक बुतशिकन (मूर्तिभंजक) बने न कि बुतफरोश (मूर्ति व्यापारी)।

गलत चित्रण

वह मथुरा की इमारतों और मंदिरों को देखकर कहता है कि इनको बनाने में 10 करोड़ दिनार और 200 साल लगे होंगे। लगता है कि ये आदमी ने नहीं जिन्नातों ने बनाए हैं। ये उसके साथ आए इतिहासकार उतबी ने लिखा है। नेहरू ने Discovery of India में सिर्फ इतना बताकर कहा कि वह एक कला प्रेमी था जबकि उतबी आगे लिखता है कि महमूद ने सारे मंदिरों को ध्वस्त कर आग लगा देने को कहा (तारीख-ए-यामिनी)।

सबसे रक्तरंजित अध्याय

ये आक्रमण हिंदू समाज के लिए कितने पीड़ादायी थे कि विल डुरांट ने अपनी किताब Story of Civilization में इस घटना उल्लेख किया है और कहा है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे रक्तरंजित अध्याय है। इसके बाद भी इस कलंक को ढोते हुए कोई राष्ट्र स्वाभिमानी नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ पुनर्स्थापना के 75वें वर्ष और 1026 में सोमनाथ के विध्वंस के सहस्राब्दी वर्ष पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने का निर्णय लिया।

संयोग या दैवयोग

आज अयोध्या में श्रीराम लला विराजमान की प्राण-प्रतिष्ठा होने और धर्म ध्वजा स्थापित करने के बाद उत्तर प्रदेश से संसद में प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का श्रीगणेश 2026 में कर रहे हैं। मतलब यह कि भारत के इतिहास का एक काल चक्र पूर्ण हो गया है। इसके निमित्त मोदी बने हैं। इसे संयोग मानिए या दैव योग यह आपकी आस्था और विवेक पर निर्भर है। यह पर्व मानो मोदीजी के नेतृत्व में digital और AI की ओर बढ़ती देश की युवा पीढ़ी को यह संदेश दे रहा है कि 'Zen-Z के युवाओ जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है।'

युवा देश, घटते मौके- क्या बढ़ती बेरोजगारी रोक रही है 'विकसित भारत 2047' की राह?

देश में पिछले कुछ वर्षों से बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इससे बड़े स्तर पर युवा श्रम शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और यह राष्ट्र के संपूर्ण विकास में भी अवरोध पैदा कर रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था को तभी संतुलित माना जाता है, जब उसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हों। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कार्यबल तथा जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहां युवाओं की आबादी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। मगर इस कार्यबल को व्यापक रूप से राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।

इसका आकलन केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी रपट से किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि देश में पंद्रह वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी दर पिछले वर्ष दिसंबर में बढ़कर 4.8 फीसद पर पहुंच गई, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 4.7 फीसद था। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी का असर ज्यादा रहा, जहां इसकी दर नवंबर में 6.5 फीसद से बढ़कर 6.7 फीसद हो गई। इससे स्पष्ट है कि सरकारी और निजी संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। रतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्किल इंडिया' जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है, लेकिन इनका असर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रहा है। कई युवा और श्रमिक वर्ग अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। कृत्रिम मेधा और डिजिटलीकरण के कारण भी रोजगार में कमी आई है। हालांकि, डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन इनमें भी विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, जो हर किसी के पास नहीं है। इसमें दोराय नहीं कि रोजगार की मांग के अनुपात में सरकारी नौकरियों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके अलावा, सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और परीक्षा प्रणाली के मुद्दे भी रोजगार हासिल करने के समान अवसरों को प्रभावित करते हैं। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में राहत की बात यह है कि वहां पिछले वर्ष नवंबर से दिसंबर के बीच बेरोजगारी दर 3.9 फीसद पर स्थिर है।

दरअसल, किसी भी देश में संपूर्ण आर्थिक विकास तभी संभव हो पाता है, जब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी तथा गरीबी, भुखमरी और सामाजिक असमानता में कमी आए तथा रोजगार की उपलब्धता और प्रति व्यक्ति खुशहाली हो। विकास का माडल ऐसा होना चाहिए, जिसमें रोजगार के अवसर, गरीबों का उत्थान और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित हो सके तथा महंगाई की दर कम रहे। सवाल है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, क्या मौजूदा परिस्थितियों की लिहाज से उसे तय समय में हासिल किया जा सकेगा! यह सच है कि बेरोजगारी दर में उतार-चढ़ाव से देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी दर में कमी लाने के लिए शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ने को प्राथमिकता दी जाए और सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं। तभी भारत सही मायने में एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा।

साप्ताहिक शहर सत्ता

भगवा लहर में ध्वस्त हुआ महाराष्ट्र निकाय का किला

महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है. महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों की कुल 2,869 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 64.51% के स्ट्राइक रेट से 1,425 सीटों पर जीत दर्ज की है. इसी तरह बीजेपी ने BMC में 66% के शानदार स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती हैं. इसके उलट कांग्रेस और अविभाजित शिवसेना के प्रदर्शन में गिरावट आई है. हालांकि, AIMIM के प्रदर्शन ने भी सभी को चौंका दिया है.इसी तरह मुंबई नगर निगम के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है, जहां बीजेपी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा और 66% के शानदार स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 89 सीटों पर जीत दर्ज की है. यहां बीजेपी ने 45.39% वोट शेयर हासिल किया है, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) ने 90 में से 29 सीटें जीती हैं.

UBT ने जीतीं 65 सीटें

वहीं, शिवसेना (UBT) 40.62% स्ट्राइक रेट के साथ दूसरे स्थान पर है. बीएमसी चुनाव में UBT ने सबसे ज्यादा 160 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां उसने 27.37% वोट शेयर के साथ 65 सीटों पर जीत हासिल की है. जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और वह केवल 15.89% स्ट्राइक रेट ही छू पाई. इसी तरह शरद पवार की एनसीपी और राज ठाकरे की मनसे भी लोगों को अपने पक्ष में करने में नाकाम रही. वह एक प्रतिशत से भी कम स्ट्राइक रेट के साथ कुछ ही सीटों पर सिमट कर रहे गए हैं.

2017 के मुकाबले बीजेपी की बढ़ी बढ़त

चुनावी आंकड़ों के अनुसार, केवल मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2017 के मुकाबले बड़ी बढ़त हासिल की है. साल 2017 में बीजेपी के पास 1,125 सीटें थीं जो अब बढ़कर 1,425 हो गई हैं. इसके उलट कांग्रेस और अविभाजित शिवसेना के प्रदर्शन में गिरावट आई है, क्योंकि पहले अविभाजित शिवसेना के पास 500 से ज्यादा सीटों थी. पर अब दोनों दलों के पास 399 सीटें हैं.

कांग्रेस से बेहतर AIMIM का प्रदर्शन

बीजेपी की तरह ही हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) ने भी 29.78% स्ट्राइक रेट के साथ 126 सीटें जीतकर पूरे राज्य में बड़ी राजनीतिक बढ़त हासिल की है.

AAP ने खोल पाई खाता

इन चुनाव परिणामों ने महाविकास अघाड़ी के घटकों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) ने 455 सीटों पर हाथ आजमाया, लेकिन उसका खाता भी नहीं खुल सका. शरद पवार की पार्टी को पूरे राज्य में केवल 36 सीटें मिलीं, जबकि अजीत पवार गुट वाली एनसीपी ने 167 सीटें जीतीं.महाराष्ट्र की इस जनादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जनादेश को सुशासन और विकास की जीत करार दिया है.

क्या होगा महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य

शिवसेना में टूट के बाद यह पहली बार था, जब महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव कराए गए. आख़िरी बार साल 2017 में बीएमसी के चुनाव हुए थे और तब नतीजे , शिवसेना के ही पक्ष में रहे थे. बीते तीन दशक से महाराष्ट्र के सबसे अहम नगर निगम यानी बीएमसी पर शिव सेना का ही प्रभुत्व रहा है.लेकिन पूरे चार साल के अंतराल पर जब इस बार चुनाव करवाए गए और अब नतीजे भी सामने हैं, तो साफ़ है कि बीजेपी ठाकरे बंधुओं पर भारी पड़ी है.बीजेपी ने 2,784 में से 1,372 सीटें जीतकर और प्रमुख सीटों पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे को पीछे छोड़कर, बीजेपी ने यह दिखा दिया है कि आने वाले तीन वर्षों में महायुति सरकार में उसी का दबदबा रहेगा. महाराष्ट्र के बाक़ी हिस्सों में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है. लेकिन मुंबई में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उद्धव ठाकरे मुख्य विपक्षी के रूप में सामने आए.नतीजे महायुति के भीतर संभावित शक्ति-संतुलन को दर्शाते हैं और साथ ही सामूहिक विपक्षी मोर्चे के रूप में महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर भी सवाल खड़े करते हैं. बीजेपी ने महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस (315 सीटें) से चार गुना और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिव सेना (394 सीटें) से तीन गुना अधिक सीटें जीती हैं.इन नतीजों ने न केवल आगे राज्य की राजनीति में शक्ति-संतुलन का संकेत दिया है बल्कि यह भी साफ़ किया है कि आने वाले चुनावों में मुख्य विपक्षी पार्टी कौन होगी.इससे शरद पवार की एनसीपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य कमज़ोर दिखाई देता है.नतीजों में शरद पवार की स्थिति कमज़ोर होती दिखी (36 सीटें), कई जगह खाता तक नहीं खोल सकी.।

त्रिपुरा चिट फंड घोटाले में 14 साल से फरार भगोड़े आरोपी गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने त्रिपुरा के चर्चित चिट फंड घोटाले में फरार चल रहे आरोपी तपन प्रमाणिक को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आरोपी तपन पिछले 14 सालों से फरार चल रहा था. अदालत ने उसे पहले से ही भगोड़ा घोषित कर रखा था.CBI ने ये केस 8 अक्टूबर, 2013 को दर्ज किया था. इस घोटाले की जांच की शुरुआत त्रिपुरा सरकार और भारत सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के आधार पर हुई थी.

इस मामले में आरोप है कि तपन प्रमाणिक, M/s M.P.S Agro-Animal Projects Ltd. नाम की कंपनी का डायरेक्टर था. उसकी कंपनी और उसके एजेंटों ने लोगों को निवेश के नाम पर लालच देकर करीब 3 से 4 करोड़ रुपये तक की रकम इकट्ठा कर ली थी. इसके बाद में ये सारा पैसा हड़प लिया गया और निवेशकों को वापस नहीं किया गया.

घोटाले की पूरी जांच होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 13 अक्टूबर, 2015 को पहली चार्जशीट दाखिल की. इसके बाद 31 मई, 2019 को एजेंसी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की. इस दौरान तपन प्रमाणिक जांच में शामिल नहीं हुआ और लगातार फरार रहा.कोर्ट ने आरोपी तपन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन वो लगातार जांच एजेंसी की पकड़ से बाहर रहा. आखिरकार 16 जनवरी, 2023 को अदालत ने चिट फंड घोटाला के मुख्य आरोपी के तौर पर औपचारिक रूप से तपन प्रमाणिक को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया. CBI ने आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए. टीम ने फील्ड में जाकर वेरिफिकेशन किया, उसके संपर्कों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली और फिजिकल सर्विलांस भी किया. आखिरकार इसी ट्रैकिंग के आधार पर CBI ने आरोपी को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से गिरफ्तार कर लिया.

जब तक धर्म भारत को चलाएगा, देश विश्व गुरु बना रहेगा : मोहन भागवत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (R S S) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार (18 जनवरी) को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जब तक धर्म भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा, देश विश्वगुरु बना रहेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वह दुनिया में कहीं और उपलब्ध नहीं है क्योंकि अन्य जगहों पर आध्यात्मिकता की कमी है. मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे वह नरेंद्र भाई हों, मैं हूं, आप हों या कोई और, हम सभी को चलाने वाली एक ही शक्ति है. अगर गाड़ी उस शक्ति से चलाई जाती है, तो कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी. वह चालक धर्म ही है. मेरे पीछे कोई नहीं है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तुम्हारी ही ताकत है. जब सृष्टि बनी तभी धर्म बना और जब तक धर्म भारत को चलाएगा, भारत विश्व गुरु बना रहेगा.

उन्होंने कहा कि पानी का धर्म बहना है, आग का धर्म जलना है. इसी तरह बेटे का कर्तव्य है, शासक का कर्तव्य है और आचरण के नियम हैं. हमारे पूर्वजों ने गहन आध्यात्मिक शोध और प्रयासों से इन कानूनों को समझा था. उन्होंने यह भी राय व्यक्त की कि एक राज्य या व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष हो

सकती है, लेकिन कोई भी इंसान या रचना धर्म के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती. उन्होंने कहा कि भारत के सामान्य जनमानस में धर्म गहरा समाया हुआ है. झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति शायद भाषण न दे पाए, लेकिन धर्म उसकी रगों में बहता है. आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हम चौकीदारी करने वाले लोग हैं. हम धर्म ग्रुप की रक्षा करते हैं. अफजल खान शिवाजी महाराज से मिलने आया था. उसने लोगों पर ज़ुल्म किए लेकिन महाराज शांत थे. किस्मत अच्छे कर्मों को परखती है. उन्होंने आगे कहा कि धर्म कभी हारता नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों-आतंकियों में मुठभेड़

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले भारतीय सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया है.

जिले के सुदूर वन क्षेत्र सिंहपुर में भारतीय सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी. सेना के अधिकारियों ने बताया कि दोपहर को चतरू क्षेत्र के मन्द्रल-सिंघूरा के पास सोननार गांव में घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई. इलाके में अतिरिक्त बलों को भेजा गया है. सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है. बताया जा रहा है कि ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े हो सकते हैं और संयुक्त अभियान के दौरान वे इलाके में फंस गए हैं. आतंकियों की मौजूदगी पता चलने के बाद पूरे क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेर लिया है ताकि आतंकी भागने में सफल न हो सकें. सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकवादियों का एक समूह इलाके में फंसा हुआ है।

टैरिफ तबतक देना होगा, जबतक ग्रीनलैड की पूरी खरीदी की डील नहीं हो जाती

ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल के विरोध करने वाले देशों को लेकर बड़ी घोषणा की है. उन्होंने 8 यूरोपीय देशों पर एक्सट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी है. साथ ही उन्होंने 8 यूरोपीय देशों से इंपोर्ट होने वाले सामान पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर टैरिफ लगाया जाएगा. उन्होंने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं होता है, तो 1 जून से यह शुल्क बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा.

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'हमने कई सालों तक डेनमार्क, और यूरोपियन यूनियन के सभी देशों, और दूसरों को टैरिफ या किसी भी तरह का पेमेंट न लेकर सब्सिडी दी है. सदियों बाद डेनमार्क के लिए वापस देने का समय आ गया है. दुनिया की शांति दांव पर है! चीन और रूस ग्रीनलैंड चाहते हैं. डेनमार्क इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. उनके पास अभी सुरक्षा के लिए दो डॉगस्लेड हैं. इनमें से एक हाल ही में जोड़ा गया है.' उन्होंने कहा, 'सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प के नेतृत्व में इस खेल में सफलतापूर्वक हिस्सा ले सकता है. कोई भी इस पवित्र जमीन के टुकड़े को हाथ नहीं लगाएगा. वो भी तब जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल सिक्योरिटी और पूरी दुनिया की सुरक्षा दांव पर लगी हो. इनके अलावा डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स और फिनलैंड ग्रीनलैंड क्यों गए हैं, इसकी वजह नहीं पता. यह हमारे गृह क्षेत्र की सुरक्षा, हिफाजत और अस्तित्व के लिए बेहद ही खतरनाक स्थिति है. ये देश बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं. उन्होंने अस्वीकार्य जोखिम पैदा कर दिया है.' ट्रंप ने कहा,'वैश्विक शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी है कि जरूरी और कड़े कदम उठाए जाएं. ताकि यह संभावित खतरनाक स्थिति जल्दी और बिना की किसी सवाल के खत्म हो जाए.'ट्रंप ने इन सभी देशों पर 1 जून 2026 से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान किया है. साथ ही 10 % टैरिफ लेने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा है कि यह टैरिफ तबतक देना होगा, जबतक ग्रीनलैड की पूरी खरीदी की डील नहीं हो जाती।

वनडे में 164, टी20 में 204 का स्ट्राइक रेट कब होगा 14 साल के वैभव का डेब्यू

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी, वो 12 साल का लड़का था जिसने बिहार के लिए डोमेस्टिक डेब्यू कर लिया था. 14 की उम्र तक आते-आते IPL और भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाल मचा चुके हैं. इन दिनों वैभव अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. केवल 18 मैचों के टी20 करियर में 3 शतक जड़ चुके हैं.

वैभव, जिस भी टीम के लिए खेलते हैं उसे तूफानी शुरुआत दिलाते आए हैं. टी20 क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट 204.37 का है, वहीं लिस्ट-A करियर में भी उन्होंने अब तक करीब 165 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. खासतौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने तबाही मचाई हुई है. उन्हें टीम इंडिया में लाए जाने की मांग उठने लगी है, लेकिन सवाल है कि क्या वैभव अभी टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं? अगर हां, तो कब तक उनका डेब्यू हो पाएगा? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

कब तक कर पाएंगे डेब्यू?

साल 2020 से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू करने को लेकर उम्र का कोई नियम नहीं था. मगर 2020 में ICC ने ऐसा नियम लागू किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए किसी खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए.वहीं वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च, 2011 को हुआ था और उनकी उम्र अभी 14 साल 297 दिन है. 68 दिनों के बाद उनकी उम्र 15 साल हो जाएगी, जिसके बाद ICC के नियम के तहत वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के योग्य हो जाएंगे. लिस्ट A क्रिकेट में उनका औसत 44.12 का है, वहीं टी20 मैचों में अब तक उन्होंने 41.23 के औसत से रन बनाए हैं.

क्या हो सकता है टीम इंडिया में सेलेक्शन?

वैभव सूर्यवंशी ने खासतौर पर सफेद गेंद की क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है. टी20 फॉर्मेट की बात करें तो उसमें संभव ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अगले कुछ समय तक ओपनिंग बल्लेबाजी का रोल निभाएंगे. वहीं नंबर-3 पर सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा अपना क्रम आगे पीछे करते रहते हैं. साफ तौर पर कहें तो अभी टी20 टीम के टॉप ऑर्डर में अभी जगह खाली नहीं है. वहीं वनडे टीम का भी यही हाल है. इसलिए वैभव सूर्यवंशी का भारतीय स्क्वाड में चयन हो भी जाता है, तो शायद अगले कुछ समय तक उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पाएगा.

भारत के खिलाफ शतक जड़ डेरिल मिचेल ने रचा इतिहास

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेरिल मिचेल का बल्ला खूब गरज रहा है. उन्होंने भारत के खिलाफ लगातार दूसरे ODI मैच में शतक जड़ दिया है. इंदौर में खेले जा रहे मैच में उन्होंने 106 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. यह भारतीय पिचों पर खेलते हुए मिचेल का भारत के खिलाफ चौथा शतक है. वो अब भारत में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने से एक कदम दूर हैं. तीसरे वनडे मैच में डेरिल मिचेल दूसरे ओवर में ही बल्लेबाजी करने आ गए थे, क्योंकि कीवी टीम ने अपने पहले 2 विकेट पारी की पहली 7 गेंदों के भीतर गंवा दिए थे. मिचेल ने ठीक दूसरे ODI की तरह एक छोर संभाले रखा और अपने वनडे करियर का 9वां शतक जड़ डाला.

भारत में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है. डिविलियर्स ने भारतीय सरजमीं पर टीम इंडिया के खिलाफ 11 पारियों में 5 शतक लगाए थे. वहीं मिचेल भारत में भारत के खिलाफ 8 वनडे पारियों में 4 शतक लगा चुके हैं. इसका मतलब भारतीय पिचों पर मिचेल हर दूसरी वनडे पारी में शतक लगा रहे हैं.

5 शतक - एबी डिविलियर्स (11 पारी)

4 शतक - डेरिल मिचेल (8 पारी)

डेरिल मिचेल 2023 ODI वर्ल्ड कप के बाद से ही भारतीय गेंदबाजों के लिए मुसीबत खड़ी करते आए हैं. वो भारत के खिलाफ अपनी पहली 4 वनडे पारियों में एक अर्धशतक तक नहीं लगा पाए थे, लेकिन टीम इंडिया के खिलाफ पिछली 7 ODI पारियों में वो 4 शतक और दो अर्धशतक लगा चुके हैं. बता दें कि मिचेल ने वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के खिलाफ 700 से अधिक रन बना लिए हैं.

मारुति सुजुकी गुजरात में खोलेगी 35000 करोड़ का प्लांट

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड गुजरात के खोरज में एक नया प्लांट बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है. कंपनी का प्लान इस प्लांट में हर साल कुल 10 लाख कारें बनाना है. इतना ही नहीं, इस नए ऑटो प्लांट के बनने से करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है. मारुति सुजुकी का गुजरात प्लांट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GIDC) द्वारा दी गई 1,750 एकड़ की जमीन पर लगाया जाएगा. कंपनी के MD श्रीयुत हिताची ताकेउची ने गांधीनगर में राज्य सरकार और ऑटोमेकर के बीच हुए एक समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इन्वेस्टमेंट लेटर सौंपा. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और मारुति सुजुकी के होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सुनील कक्कड़ भी मौजूद रहे।

देश भर के टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगा कैश, सिर्फ FASTag या UPI से होगा पेमेंट

नई दिल्ली। देश के हाइवे पर सफर करने के तौर-तरीके बदल रहे हैं. इस क्रम में एक और नया बदलाव होने जा रहा है. दरअसल, हाइवे पर टोल चुकाने का तरीका ही पूरी तरह से बदलने जा रहा है. केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट बंद करने की तैयारी में है. यानी कि अब लंबी कतारों में लगे रहने के झंझट, खुले पैसे के लिए झिकझिक, टोल बूथ पर रुककर चलने की मजबूरी के दिन जाने वाले हैं. नई व्यवस्था के तहत, ड्राइवरों को टोल चार्ज सिर्फ FASTag या UPI के जरिए ही देना होगा, जो डिजिटल ट्रैवल की दिशा में बढ़ाया जाने वाला एक बड़ा कदम है. सरकार का मानना है कि इस नए फैसले से न सिर्फ पैसे की बचत होगी, बल्कि सफर में समय भी कम लगेगा और कहीं आना-जाना भी आसान होगा.

टोल प्लाजा को कैशलेस बनाने की तैयारियां पहले से ही चल रही थीं. फिलहाल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मिलने के इंतजार है, जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. इस फैसले का मकसद टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम को कम करना है. डिजिटल पेमेंट होने से गाड़ियों को अब कैश ट्रांजैक्शन के लिए रुकना नहीं पड़ेगा या चेंज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इससे टोल पॉइंट पर बार-बार ब्रेक लगाने और स्पीड बढ़ाने से फ्यूल की भी बचत होगी. पेमेंट डिजिटली होने से इसका एक रिकॉर्ड भी बना रहेगा.

टी20 में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक

नई दिल्ली। टी20 क्रिकेट में आए दिन चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिलती रहती हैं. लेकिन क्या आपने

टी20 इंटरनेशनल में ऐसी पारी देखी है, जब किसी बल्लेबाज ने 351.21 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हों. ऐसी तूफानी पारी जिसमें 18 छक्के और 24 चौके लगे हों. टी20 इंटरनेशनल में ये कारनामा भारतीय मूल के साहिल चौहान ने डेढ़ साल पहले यानी 17 जून, 2024 को किया था. एस्टोनिया के लिए खेलने वाले साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है.हरियाणा के पिंजौर में जन्मे साहिल चौहान यूरोप में क्रिकेट का एक बड़ा नाम है. भारतीय मूल के साहिल एस्टोनिया की ओर से क्रिकेट खेलते हैं. उनकी पहचान एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज के रूप में है. साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में साहिल ने महज 27 गेंद में शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 41 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 144 रन की तूफानी पारी खेली. जिसमें उन्होंने 18 गगनचुंबी छक्के लगाएं थे. ये वो आंकड़े हैं, जो साहिल चौहान के नाम दर्ज हैं.

भारत-EU के बीच फाइनल होने जा रहा FTA

नई दिल्ली। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता के बीच भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील फाइनल होने के करीब पहुंच चुकी है. उम्मीद है कि 27 दिसंबर को इस डील पर साइन होगी. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत और EU ने 24 में से 20 चैप्टर पर साइन कर दिए हैं और उनका लक्ष्य इस महीने के आखिर में EU नेताओं के भारत आने से पहले डील को पूरा करना है. यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, उर्सुला वॉन डेर लेयेन 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. दोनों 27 जनवरी को 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी करेंगे. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी औपचारिक घोषणा की।

1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला यूनियन बजट 2026-27

मिडिल क्लास को टैक्स, घर और नौकरी पर राहत की उम्मीद

नई दिल्ली। जैसे-जैसे बजट का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे आम नौकरीपेशा और मिडिल क्लास परिवारों की उम्मीदें भी बढ़ने लगी हैं. हर साल 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट सिर्फ सरकार के खर्च और कमाई के बारे में ही जानकारी नहीं देती. बल्कि इसका असर लोगों की सैलरी, टैक्स और बचत पर पड़ता है. यही वजह है कि इस दिन पर पूरे देश की नजर वित्त मंत्री के भाषण पर टिकी रहती है.

1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला यूनियन बजट 2026-27 कई मायनों में खास माना जा रहा है. मौजूदा इनकम टैक्स कानून के तहत पेश होने वाला यह आखिरी बजट है. सरकार अगले वित्त वर्ष से नया Income Tax Act 2025 लागू करने की तैयारी में हैं. जिससे दशकों पुराने टैक्स नियम बदल जाएंगे. यही कारण है कि करदाताओं को इस बजट से कई बड़ी राहतों की उम्मीद हैं. आइए जानते है भारतीय मिडिल क्लास सरकार से कौन-कौन सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं.....बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए सबसे भारी बोझ घर और इलाज से जुड़ा खर्च बनता जा रहा हैं. ऐसे में टैक्सपेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि, टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ-साथ सरकार रोजमर्रा के जरूरी खर्चों पर छूट देकर उन्हें राहत दें. मौजूदा समय में होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की जो छूट मिलती है. यह प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के मुकाबले काफी कम मानी जा रही है.वहीं मिडिल क्लास की यह भी मांग है कि अगर सरकार न्यू टैक्स रिजीम को आगे बढ़ाती हैं, तो उसमें कुछ अहम कटौतियों को शामिल किया जाए. खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन से जुड़ी टैक्स छूट की उम्मीद मिडिल क्लास कर रहा है. ताकि लोग इलाज और घर जैसी जरूरतों के लिए बिना ज्यादा दबाव के बचत और निवेश कर सकें. पिछले बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम से टैक्सपेयर्स को राहत देने का ऐलान किया था. 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई थी. हालांकि, इस दौरान वे टैक्सपेयर्स खुद को नजरअंदाज महसूस करने लगे, जो अब भी पुराने टैक्स सिस्टम पर टिके हुए हैं और उसी को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं.ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करने वाले टैक्सपेयर्स पीएफ, इंश्योरेंस और होम लोन जैसी बचत योजनाओं पर निर्भर रहते हैं।

साप्ताहिक शहर सत्ता

'सम्मान नहीं दे सकते तो मत बुलाओ'

बालोद में कुर्मी समाज के सम्मेलन में भड़के भूपेश बघेल

बालोद। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को बालोद जिला मुख्यालय में आयोजित कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक सम्मेलन में अपने तीखे तेवरों के कारण चर्चा में रहे। सरदार पटेल मैदान में आयोजित इस सामाजिक समागम में उस वक्त भारी सन्नाटा पसर गया, जब बघेल ने मंच से ही आयोजकों और समाज के पदाधिकारियों को खरी-खोटी सुना दी।

विवाद की स्थिति तब बनी जब भूपेश बघेल अपने भाषण के दौरान प्रदेश की वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार की नीतियों और धान खरीदी की अव्यवस्थाओं पर प्रहार कर रहे थे। इसी बीच मंच पर मौजूद कुछ पदाधिकारियों ने उन्हें टोकते हुए यह कह दिया कि "यह सामाजिक मंच है, यहाँ राजनीति न करें।"

पदाधिकारियों की यह टोक-टाकी भूपेश बघेल को नागवार गुजरी और वे मंच पर ही भड़क गए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि वे किसानों के हित की बात कर रहे हैं और समाज के अधिकांश लोग किसान ही हैं, ऐसे में यह राजनीति कैसे हो गई? उन्होंने आयोजकों को सीधे तौर पर नसीहत देते हुए कहा कि यदि आप किसी अतिथि को सम्मान नहीं दे सकते, तो उसे बुलाया ही मत करो। बघेल ने यहाँ तक कह दिया कि मंच पर बैठे दूसरे दल के लोगों को उनकी बातों से 'मिर्ची' लग रही है, लेकिन वे दबने वाले नहीं हैं। संबोधन खत्म करने के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि जिन्हें उनकी बातों से ठेस पहुंची है, उनके लिए वे कोई खेद व्यक्त नहीं करेंगे।

बघेल का दोटूक अंदाज

- "बुलाए हो तो सम्मान देना सीखो, टोकना शिष्टाचार नहीं है।"
- "किसानों के दुख-दर्द को राजनीति कहना गलत है।"
- "मैं अपनी बातों के लिए किसी से माफी या खेद प्रकट नहीं करूँगा।"

विवाद की वजह

जब 'धान' पर छिड़ी 'जंग' असल में भूपेश बघेल मंच से बालोद में धान से भरे ट्रक गायब होने और चूहों द्वारा करोड़ों का धान खा जाने जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर रहे थे। आयोजकों का प्रयास था कि कार्यक्रम को गैर-राजनीतिक रखा जाए, लेकिन बघेल का तर्क था कि समाज और किसान अलग नहीं हैं। यही वैचारिक मतभेद मंच पर सार्वजनिक बहस और नाराजगी में बदल गया।

हालांकि, इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद कुर्मी क्षत्रिय समाज के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र देशमुख ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया से कहा कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी बात रखी और वे खुश होकर गए हैं। लेकिन मंच पर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की, वह अब पूरे प्रदेश के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। कार्यक्रम के दौरान बघेल ने मीडिया के उन सवालों को भी टाल दिया जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (PCC) के बदले जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं।

भूपेश सरकार में कदम-कदम पर महिलाओं का आत्मसम्मान रौंदा गया: डॉ. किरण बघेल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. किरण बघेल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण करके कांग्रेस अब अपराधों को लेकर सियासी पाखण्ड का प्रदर्शन कर रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह द्वारा प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए डॉ. बघेल ने कहा कि प्रदेश में हो रहे अधिकांश अपराधों में कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं की संलिप्तता सामने आ रही है, इसलिए कांग्रेस को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबाँ में झाँकना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया था, जहाँ कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी और पुलिस प्रशासन का उपयोग केवल अवैध उगाही के लिए किया जा रहा था।

डॉ. बघेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में आदिवासियों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में प्रदेश देश में शीर्ष पर था और अपराधियों को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने जांजगीर के पेण्ड्री डकैती कांड का हवाला देते हुए कहा कि पकड़े गए हथियार क्षेत्रीय विधायक के घर से मिले हैं, जो कांग्रेस के आपराधिक चरित्र को उजागर करता है। भाजपा प्रवक्ता ने गुंजन सिंह को नसीहत दी कि वे महिलाओं के सम्मान पर घड़ियाली आँसू बहाने के बजाय अपनी ही पार्टी के भीतर महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी और कांग्रेसी नेताओं द्वारा नारी शक्ति पर की गई अश्लील टिप्पणियों पर जवाब दें।

महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी, भाजपा महिला मोर्चा ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की रायपुर शहर जिला अध्यक्ष कृतिका जैन के नेतृत्व में शनिवार को प्रदेश प्रवक्ता डॉ किरण बघेल, शताब्दी पांडे व महिला मोर्चा की पूरी टीम आज मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर एसपी ऑफिस कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज कराई।

भाजपा महिला नेत्रियों ने ज्ञापन में कहा है कि अजा-अजजा एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अश्लील टिप्पणी कर दतिया (मप्र) के कांग्रेस विधायक बरैया ने समस्त नारी-शक्ति का अपमान किया है। ज्ञापन में बरैया के अजा-अजजा व पिछड़ा वर्ग की महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार को धर्मग्रंथों से जोड़कर की गई टिप्पणी को अश्लीलता की पराकाष्ठा बताते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी एक सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। भाजपा महिला मोर्चा ने आरोपी कांग्रेस विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं व एससी-एसटी एवं ओबीसी कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान डॉ. किरण सिंह, प्रियंका गिरी, रजनी शिंदे, माया शर्मा, शमा भारती, शिवानी आदि की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।

टीएमसी शासन 'भय और राजनीतिक हिंसा' की प्रयोगशाला: संतोष पाण्डेय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और वहाँ सरकारी कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं हैं। श्री पाण्डेय ने जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अशोक दास की मौत के लिए टीएमसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी अशोक दास को टीएमसी नेताओं ने वोटर लिस्ट से अवैध नाम न हटाने के लिए धमकाया और उनकी पत्नी व बच्चे को नुकसान पहुँचाने की चेतावनी दी। इसी मानसिक दबाव के कारण उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने टीएमसी की नई परिभाषा बताते हुए कहा कि इसका अर्थ अब 'तुष्टिकरण, माफिया और क्राइम कल्चर' हो गया है। श्री पाण्डेय ने उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ सरकारी कार्यालय में आगजनी और अधिकारियों पर हमला कर चुनावी प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है, ताकि फर्जी मतदाताओं के दम पर चुनाव जीता जा सके। सांसद पाण्डेय ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है।

देश की राजनीति में कहीं परिवारवाद है, तो वह कांग्रेस पार्टी में है

परिवारवाद के आरोपों पर सीएम साय का पलटवार, कहा- कांग्रेस में ही है असली परिवारवाद

रायपपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए परिवारवाद के आरोपों पर कड़ा जवाब देते हुए उन्हें पूरी तरह असत्य बताया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि देश की राजनीति में कहीं परिवारवाद है, तो वह कांग्रेस पार्टी में है। मुख्यमंत्री साय ने भाजपा की संगठनात्मक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी में हर तीन वर्ष में लोकतांत्रिक तरीके से संगठनात्मक चुनाव कराए जाते हैं। इन चुनावों के माध्यम से स्थानीय समिति से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक दायित्वों में बदलाव होता है।

इससे नए कार्यकर्ताओं को आगे आने का अवसर मिलता है और संगठन में पारदर्शिता व ऊर्जा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां पद से अधिक संगठन और विचारधारा को महत्व दिया जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नेतृत्व का चयन ही भाजपा को अन्य राजनीतिक दलों से अलग और मजबूत बनाता है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट और सख्त संदेश देते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा।

गौरतलब है कि बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में 17–18 जनवरी से डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कई मुठभेड़ हुई हैं।

अब तक कुल 6 माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें 4 महिला नक्सली शामिल हैं। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने 2 AK-47, 1 INSAS राइफल, 2 .303 राइफल और 1 कार्बाइन सहित कुल 6 अत्याधुनिक हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मारे गए माओवादियों में नेशनल पार्क एरिया कमेटी के कुख्यात कैडर शामिल हैं। अब तक जिनकी पहचान हुई है, उनमें DVCM दिलीप बेड़जा, ACM माड़वी कोसा, ACM लक्खी मड़काम और PM राधा मेट्टा शामिल हैं, जबकि शेष दो माओवादियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

छत्तीसगढ़ की धरा पर साहित्यकारों का महाकुंभ

देशभर के 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे

छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय पटल पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से रायपुर साहित्य उत्सव–2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह तीन दिवसीय साहित्यिक महोत्सव 23 से 25 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित होगा। यह उत्सव छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा, लोक परंपराओं और साहित्यिक चेतना को नई पीढ़ी से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। देशभर से प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, कथाकार, विचारक, कलाकार, पत्रकार, रंगकर्मी और साहित्य प्रेमी इस आयोजन में सहभागिता करेंगे। रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन नवा रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक होगा, जिसमें देश भर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होंगे। राज्य स्थापना के रजत वर्ष पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा इस आयोजन की परिकल्पना की गई थी। उनकी यह परिकल्पना अब साकार रूप लेने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो का अनावरण किया।

साहित्य, संवाद और संस्कृति का संगम

रायपुर साहित्य उत्सव–2026 का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजना, उसे एक व्यापक मंच प्रदान करना तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों, पाठकों और रचनाकारों को एक साझा संवाद से जोड़ना है। उत्सव के दौरान साहित्यिक संवाद, विचार-मंथन, समकालीन विषयों पर परिचर्चाएँ, कविता पाठ, कथा सत्र, पुस्तक विमोचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ एवं कला-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन न केवल साहित्यिक अभिरुचि को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विमर्श को भी नई दिशा प्रदान करेगा।

कला के लिए ओपन माइक सत्र होगा आयोजित

रायपुर साहित्य उत्सव–2026 के अंतर्गत ओपन माइक सत्र का विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आम नागरिकों, युवाओं एवं नवोदित रचनाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का मंच मिलेगा। कविता, कहानी, विचार, गीत, नाट्य अंश अथवा अन्य रचनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से प्रतिभागी अपनी सृजनात्मक क्षमता को नई उड़ान दे सकेंगे। यह सत्र साहित्य, आत्म-अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास होगा।

विद्यार्थियों और युवाओं में बढ़ेगी साहित्य के प्रति रुचि

छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्रों एवं युवाओं में साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से राज्य के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में रायपुर साहित्य उत्सव–2026 की जानकारी व्यापक रूप से साझा की जा रही है। युवा पीढ़ी को साहित्य, भाषा और संस्कृति से जोड़ने की दिशा में यह उत्सव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उत्सव स्थल तक निःशुल्क बस सेवा

रायपुर साहित्य उत्सव के दौरान आम नागरिकों, साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में निःशुल्क बस सेवा संचालित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवहन की असुविधा के कारण कोई भी व्यक्ति इस महत्वपूर्ण साहित्यिक आयोजन में भाग लेने से वंचित न रह जाए। निःशुल्क बस सेवा से शहरवासियों को उत्सव स्थल तक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन की सुविधा मिलेगी। यह निःशुल्क बस सेवा 23, 24 और 25 जनवरी 2026—तीन दिनों तक लगातार संचालित की जाएगी। इन तीनों दिनों में बसों का संचालन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, जिससे आमजन बिना किसी अतिरिक्त खर्च के रायपुर साहित्य उत्सव में शामिल हो सकेंगे। यह व्यवस्था विशेष रूप से विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों और साहित्य प्रेमियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 15 बसें इस निःशुल्क सेवा के अंतर्गत चलाई जाएंगी। ये बसें उत्सव स्थल तक आने और लौटने—दोनों दिशाओं में संचालित होंगी, ताकि दर्शकों को कार्यक्रम समाप्ति के बाद भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। बसों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की गई है कि भीड़ के समय भी सुचारु आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। शहर के अधिकतम क्षेत्रों को इस सुविधा से जोड़ने के लिए बस संचालन हेतु कुल 6 प्रमुख रूट तय किए गए हैं।

वीबी-जी राम जी : गांव को श्रम से समृद्धि तक ले जाने की नई गारंटी

रायपुर। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब गांव मजबूत होते हैं, तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। इसी मूल भावना को साकार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत–ग्राम गारंटी अधिनियम 2025 (वीबी-जी राम जी) को लागू किया गया है। यह योजना ग्रामीण भारत के लिए केवल एक रोजगार कार्यक्रम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और स्थायी विकास की मजबूत आधारशिला है। वीबी-जी राम जी के माध्यम से गांवों में अब 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है। यह पहल ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने, पलायन रोकने और गांव की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन रूप से सशक्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध हो रही है।

वीबी-जी राम जी के प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 40 लाख से अधिक ग्रामीण श्रमिक परिवारों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। राज्य के आदिवासी, वनांचल एवं कृषि-प्रधान क्षेत्रों में यह योजना आजीविका सुरक्षा का सशक्त आधार बनेगी। रोजगार के बढ़े हुए दिवसों से ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, मौसमी बेरोजगारी में कमी आएगी, शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले पलायन में गिरावट दर्ज होगी तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा। धमतरी जिले में वीबी-जी राम जी के अंतर्गत अनुमानित 1 लाख 85 हजार से 2 लाख ग्रामीण श्रमिकों को प्रतिवर्ष रोजगार का लाभ प्राप्त होगा। जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा जल संरक्षण, तालाब निर्माण, ग्रामीण सड़क, गोदाम, सिंचाई संरचना, हाट बाजार तथा विभिन्न प्रकार के शेड निर्माण जैसे कार्यों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। इन कार्यों से गांवों में स्थायी एवं उपयोगी संपत्तियों का निर्माण होगा, कृषि और ग्रामीण व्यापार को मजबूती मिलेगी, महिलाओं एवं युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा ग्रामीण परिवारों की दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

वीबी-जी राम जी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें रोजगार के साथ-साथ कौशल विकास को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। श्रमिकों को जल प्रबंधन, निर्माण, रखरखाव, भंडारण तथा तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल श्रमिक ही नहीं, बल्कि स्थानीय उद्यमी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी मिलेगी, वहीं युवाओं को गांव में ही प्रशिक्षण एवं कार्य उपलब्ध होने से पलायन की मजबूरी में कमी आएगी।

इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को विकास की धुरी के रूप में सशक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। ग्राम सभा की सहमति से कार्यों का चयन, पंचायत द्वारा क्रियान्वयन, अनिवार्य सोशल ऑडिट, समय पर काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता तथा मजदूरी भुगतान में देरी होने पर मुआवजे जैसे प्रावधानों से योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।

बारनवापारा अभयारण्य में "बर्ड सर्वे" 200 से अधिक प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज

बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में 16 से 18 जनवरी 2026 तक "बर्ड सर्वे 2026" का आयोजन किया गया। सर्वे के दौरान पक्षियों की अच्छी विविधता देखने को मिली। अब तक प्राप्त डेटा के अनुसार इस सर्वे में लगभग 202 पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।

इस सर्वे में देश के 11 राज्यों महाराष्ट्र, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, केरल एवं कर्नाटक से आए 70 प्रतिभागियों, 12 वॉलंटियर्स, विशेषज्ञों एवं फोटोग्राफर्स सहित लगभग 100 लोगों की सहभागिता रही। यह बर्ड सर्वे केवल बारनवापारा अभ्यारण्य तक सीमित न होकर उसके आसपास से जुड़े कोठारी, सोनाखान एवं देवपुर परिक्षेत्रों में भी किया जा रहा है। सर्वे के दौरान प्रतिभागियों द्वारा संग्रहित पक्षी आंकड़े वैश्विक डाटाबेस का हिस्सा बनेंगे। अभयारण्य क्षेत्र में जैव विविधता का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण, बर्डिंग कल्चर एवं इको पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगा। सर्वे में प्रमुख विशेषज्ञों में डॉ. हकीमुद्दीन एफ. सैफी, डॉ. जागेश्वर वर्मा, मोहित साहू एवं सोनू अरोरा की सहभागिता रही। सर्वे के आकर्षण बने प्रमुख प्रजातियां- इस सर्वे में विशेष रूप से कुछ प्रजातियाँ प्रतिभागियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहीं, जिनमें बार-हेडेड गूज उल्लेखनीय रही, जो प्रायः मध्य एशिया के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्रजनन करती है तथा सर्दियों में भारत सहित दक्षिण एशिया के जलाशयों और खेतों में देखी जाती है। इसी प्रकार आर्द्र घासभूमि, धान के खेतों, दलदली क्षेत्रों एवं नदी किनारे पाए जाने वाले ग्रे-हेडेड लैपविंग, शिकारी पक्षी प्रजाति पेरेग्रिन फाल्कन, ब्लू-कैप्ड रॉक थ्रश, यूरेशियन स्पैरोहॉक,वन पारिस्थितिकी में बीज प्रसार के लिए महत्वपूर्ण माना जाने वाला ऑरेंज-ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन का अवलोकन भी आकर्षण का केंद्र बना।

कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी, 19 राइस मिलों पर कार्रवाई

मुंगेली जिले में कस्टम मिलिंग में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले की 14 राइस मिलों को सील करने के साथ ही 12 हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है। यह कार्रवाई राज्य आईसीसीसी से प्राप्त अलर्ट तथा मुख्य सचिव विकासशील के निर्देशानुसार की गई। राईस मिलों के जांच में ओवरलोडिंग, रिसायक्लिंग तथा कस्टम मिलिंग में गंभीर गड़बड़ियां पकड़ में आई। जांच की कार्रवाई में उपलेटा राइस मिल, नवागांव घुठेरा रोड स्थित नेशनल दाल मिल, पंडरिया रोड स्थित वर्धमान मिलिंग इंडस्ट्रीज, जैन राइस इंडस्ट्रीज तथा नवकार दाल उद्योग में कस्टम मिलिंग में अनियमितता पाई गई, जहां से 12 हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया।

वॉर, पॉलिटिक्स और पौराणिक कथाएं

2026 में बदलने वाला है भारतीय सिनेमा का रोल

इस साल बड़े-बड़े फ्रैंचाइजी सीक्वल, माइथोलॉजी पर आधारित मेगा प्रोजेक्ट्स, युद्ध और राजनीति से जुड़े ड्रामा, और नॉस्टैल्जिया, सब एक ही साल में दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए तैयार हैं। कुछ फिल्मों की रिलीज डेट फिक्स है, कुछ अभी संभावित हैं और कुछ पर सस्पेंस बरकरार है। 2026 भारतीय सिनेमा के लिए किसी प्रेशर कुकर साल से कम नहीं होने वाला। बड़े-बड़े फ्रैंचाइजी सीक्वल, पौराणिक महागाथाएं, युद्ध आधारित फिल्में, पॉलिटिकल ड्रामा और नॉस्टैल्जिया से भरी कहानियां, सब एक ही साल बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं। कुछ फिल्मों की रिलीज डेट फिक्स है, कुछ अनुमानित हैं और कुछ अब भी रहस्य बनी हुई हैं। आइए बिना किसी घुमाव-फिराव के जानते हैं 2026 की सबसे ज्यादा चर्चित भारतीय फिल्मों की पूरी लिस्ट।

बॉर्डर 2

सनी देओल की आइकॉनिक वॉर फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल एक बार फिर देशभक्ति का ज्वार लाने को तैयार है। फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म बड़े पैमाने पर युद्ध, इमोशन और बलिदान की कहानी कहेगी।
रिलीज: 23 जनवरी 2026

ओ रोमियो

शाहिद कपूर की यह फिल्म एक मल्टी-स्टारर प्रोजेक्ट है, जिसमें नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी और तृप्ति डिमरी जैसे दमदार कलाकार शामिल हैं। 'ओ रोमियो' एक इंटेंस ड्रामा मानी जा रही है, जिसकी कहानी और टोन को लेकर काफी उत्सुकता है।
रिलीज: 13 फरवरी 2026

धुरंधर 2

पहली फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद 'धुरंधर 2' की कहानी और भी गहरी और खतरनाक बताई जा रही है। अंडरकवर एजेंट हम्ज़ा अली मजारी पाकिस्तान के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में मिशन पर है। यह फिल्म हाई-स्टेक थ्रिल और जियो-पॉलिटिकल टेंशन से भरपूर होगी।
रिलीज: 19 मार्च 2026

टॉक्सिक

यश स्टारर 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' एक पीरियड गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर है। कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसे नाम इसे एक मेगा-स्केल प्रोजेक्ट बनाते हैं। स्टाइल, हिंसा और पावर प्ले- तीनों का जबरदस्त मिश्रण।
रिलीज: 19 मार्च 2026

बैटल ऑफ गलवान

सलमान खान इस फिल्म में 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित किरदार निभा रहे हैं। भारतीय सेना के साहस और बलिदान को दिखाने वाली यह फिल्म देशभक्ति सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मानी जा रही है।
एक्सपेक्टेड रिलीज: 17 अप्रैल 2026

अल्फा

आलिया भट्ट और शरवरी की यह फिल्म एक रॉ, ब्रूटल एक्शन थ्रिलर है। बॉबी देओल निगेटिव रोल में नजर आएंगे। 'अल्फा' को फीमेल-लेड एक्शन सिनेमा का बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है।
एक्सपेक्टेड रिलीज: 17 अप्रैल 2026

दृश्यम 3

अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के रोल में लौटेंगे। 'दृश्यम 3' में कहानी और भी बड़ी, दांव और भी ऊंचे और खेल और भी खतरनाक होगा।
रिलीज: 2 अक्टूबर 2026

रामायण पार्ट 1

भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक। रणबीर कपूर (राम), साई पल्लवी (सीता), यश (रावण) और सनी देओल (हनुमान) के साथ यह फिल्म माइथोलॉजी को नए विजुअल स्केल पर पेश करेगी।
एक्सपेक्टेड रिलीज: 8 नवंबर 2026

लव एंड वॉर

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की लव ट्राएंगल कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि में सेट है। इमोशन, रोमांस और संघर्ष तीनों का ग्रैंड सिनेमैटिक ट्रीट।
एक्सपेक्टेड रिलीज: 14 अगस्त 2026

सामाजिक सरोकार को जीवन का आधार बनाया पं. छेदीलाल पाण्डेय ने

डॉ. राजेश पाण्डेय

अपने विद्यार्थी जीवन में भारतीय कांग्रेस नेताओं से प्रभावित होकर स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर का स्नेह प्राप्त कर इस क्षेत्र का कुशल नेतृत्व किए। सन 1937-38 में जिला शिक्षा समिति ने आपको शालेय शिक्षा समिति का सदस्य मनोनीत किया।

पं.छेदीलाल पाण्डेय का जन्म वर्तमान मल्हार ग्राम में 1 जुलाई सन 1916 को हुआ था। आपने भारतीय संस्कृति परम्परा का पोषण करते हुए गुरु धर्म का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया तथा कुशल शिक्षक के रूप में ख्याति अर्जित की। 1934-35 में आप अपने विद्यार्थी जीवन में भारतीय कांग्रेस नेताओं से प्रभावित होकर स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर का स्नेह प्राप्त कर इस क्षेत्र का कुशल नेतृत्व किए। सन 1937-38 में जिला शिक्षा समिति ने आपको शालेय शिक्षा समिति का सदस्य मनोनीत किया। भारत सेवक समाज की ओर से 1961 में पूना, बिहार और बिलासपुर के क्षतिग्रस्त बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ सामाजिक सेवाएं प्रदान की। आपके प्रयास से केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना मल्हार में कराई गई। उक्त संग्रहालय में अनेक दुर्लभ पाषाण प्रतिमाएं संग्रहित हैं। अखिल भारतीय भारतीय कांग्रेस अधिवेशन जबलपुर में आप शीर्षस्थ नेताओं के संपर्क में रहे। रायपुर में आयोजित भूदान सर्वोदय सम्मेलन में संत विनोबा भावे से आशीर्वाद प्राप्त कर सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े। आप बिलासपुर संभाग पुरातत्व परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। आपने जन जागरण के माध्यम से शिक्षा और समाज को जीवन भर जोड़ने में अपनी महती भूमिका निभाई।

नंदावत हे अब लमसेना परथा

लालेश्वर सिन्हा

कोनो कुंवारा लइका ह बिहाव होय के बाद अपन सास ससुर घर जाके रहीथे आऊ उहीचे रहीके कमाथे खाथे वोला लमसेना कहे जाथे। पहली देखे म आवत रीहिस कि गांव के गोटिया या बड़े मन जेकर एके झन बेटी रहय बोमन दमाद ल लमसेना रखय। गरीबहा घर के लइका बर ए परथा ह बने हो जाए। वोला बने द्वार मिल जात रिहिस। इज्जत घलव मिलत रोहिस। फेर देखे म आवत रीहिस कि लमसेना दमाद ह अपन ससुरार में जादा अधिकार नी जमा पावत रीहिस। काबर कि सास ससुरार के पूंजी में रहत रोहिस। खेती बारी, घर दुवार के देख रेख करना, जीयत भर ले सास ससुर के सेवा जतन करना इही लमसेना के बुता राहय। गांव म काकरो घर लमसेना तेला पूरा गांव वोला लमसेना कहय। अइसन बिहाव ह दूनो पक्ष के आपसी सहमति ले होवत रोहिस। आजकाल अइसन परथा के चलागन ह अब देखे बर नी मिलय। कुछ कुछ जगा पहली के लमसेना मन भले देखे बर मिल जथे। समाज में ए परथा ह आने वाला दिन पूरा बंद हो जाहि लगथे।

रमदहा प्रपात में प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा

कोरिया जिला मुख्यालय से 130 कि मी दूरी पर बैकुंठपुर, कठौतिया, चुटकी और भंवरखोल होते हुए मदहा प्रपात पहुंचा जाता है। बनास नदी पर चारों ओर पहाड़ों तथा जंगल से घिरा सुंदर इस प्राकृतिक स्थान में गर्मियों के दिनों में भी पर्याप्त पानी रहता है।

श्यामवर्णीय चट्टानों से घिरा यह पर्वत जिसमें पानी रिसकर तथा प्रपात के रुप में लगभग 70 फीट ऊंचाई से गिरता है तथा एक बड़े तालाब अथवा झील में एकत्रित होकर पत्थरों से होता आगे बढ़ता है। बरसात के दिनों में यह स्थल और मनोरम हो जाता है। यहां एक शिवजी का प्राचीन मंदिर है जिसकी मान्यता भी अधिक है। रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ होने के साथ ही एक छोटी नदी भी रास्ते में होने के कारण पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है फिर भी यहां की खूबसूरती को देखने पहुंचते ही हैं।

आदिवासियों का बिना साज सज्जा दंडार नृत्य

कुसुमलता सिंह

आदिवासी दंडार नृत्य में पहला नमन हनुमान जी को, दूसरा नमन बिरसन देव, तीसरा नमन बड़ादेव और चौथा नमन गणेश जी को करते हैं। बैगा, भील, मुरिया, कोरकू, कोल और माडिया नृत्य के समय कोई साज सज्जा नहीं करते। पर्व तथा अन्य अवसरों पर किए जाने वाले नृत्यों में भी साज सज्जा नहीं करते। इसलिए इन्हें किसी भी समय नृत्य करने में दिक्कत नहीं होती। इस कारण इनके नृत्य अत्यधिक आकर्षक और दर्शनीय होते हैं। जनजातीय नृत्य आद्य कला के प्रमाणित दस्तावेज है। आधुनिक प्रभावों के कारण निरंतर बदलती जीवन शैली के कारण आदिम नृत्यों में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। फिर भी अभी ऐसी कई आदिम जनजातियों में कमार, कोरवा, अबूझमाडिया ने अपनी पारंपरिक शैली में परिवर्तन होने से बचाया है। आदिम नृत्यों में आनंद की अभिव्यक्ति मुद्राओं, प्रतीकों और लय ताल की तन्मयता में अधिक होती है।

साप्ताहिक शहरसत्ता

रायपुर का 'सुपरकॉप' कौन?

4 जिले बनाम 22 थाने: रुतबे की जंग में फंसी नई पुलिसिंग व्यवस्था, आईएएस-आईपीएस लॉबी में ठनी

विशेष संवाददाता/शेख आबिद
मोबाईल नंबर 8109802829

रायपुर। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था के इतिहास में 23 जनवरी की तारीख एक मील का पत्थर साबित होने वाली थी, लेकिन इस ऐतिहासिक बदलाव से पहले ही राजधानी का पुलिस महकमा 'असमंजस के चक्रव्यूह' में फंस गया है। सवाल केवल शहर की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि सवाल उस 'कुर्सी' की ताकत का है, जिसके इर्द-गिर्द प्रतिष्ठा की नई लकीरें खींची जा रही हैं। रायपुर के 'पहले कमिश्नर' की ताजपोशी से पहले विभाग के भीतर एक ऐसा धर्मसंकट खड़ा हो गया है जिसने पुलिसिंग के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

प्रतिष्ठा का प्रश्न: 4 जिलों की सल्तनत या 22 थानों का किला?

आईपीएस लॉबी के भीतर इस समय सबसे बड़ी बहस 'पॉवर बैलेंस' को लेकर है। अफसरों के सामने दो विकल्प हैं:

- **कमिश्नर का पद:** रायपुर शहर के केवल 22 थानों की कमान।
- **रेंज आईजी का पद:** रायपुर देहात (नवा रायपुर समेत) के 11 थाने और इसके साथ धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद व गरियाबंद जैसे 4 बड़े जिलों का साम्राज्य।

वरिष्ठ अधिकारियों के बीच यह चर्चा आम है कि क्या 4 जिलों पर राज करने वाले आईजी का रुतबा, महज 22 थानों के कमिश्नर से बड़ा होगा? इस गणित ने बड़े अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। अधिकारियों को डर है कि कमिश्नरी के सीमित दायरे के कारण उनकी हैसियत 'सुपर एसपी' जैसी होकर न रह जाए।

कमिश्नर की रेस: अनुभव बनाम कार्यकाल

पहले पुलिस कमिश्नर के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं:

रामगोपाल गर्ग (आईजी, दुर्ग)

सीबीआई में 7 साल का अनुभव और नियमों की कड़ी समझ उन्हें सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। उनकी छवि एक 'क्लीन' ऑफिसर की है, जो नई व्यवस्था को पारदर्शी शुरुआत दे सकते हैं।

संजीव शुक्ला (आईजी, बिलासपुर)

रायपुर के पुराने नेटवर्क और स्थानीय तासीर की गहरी समझ इनके पक्ष में है। हालांकि, जनवरी 2027 में उनकी सेवानिवृत्ति एक तकनीकी पेच फंसा सकती है, क्योंकि उनके पास केवल 11 महीने का समय बचेगा। इनके अलावा अजय यादव और बद्री नारायण मीणा जैसे नाम भी रेस में हैं, जो रायपुर की नब्ज से वाकिफ रहे हैं।

ज्वाइंट कमिश्नर प्रणाली में एसएसपी रैंक के अधिकारी होंगे

कमिश्नरेट प्रणाली में 'ज्वाइंट कमिश्नर' का पद गले की हड्डी बन गया है। इस पद पर डीआईजी रैंक के अधिकारी की नियुक्ति होनी है। वर्तमान में जो अधिकारी डीआईजी रैंक पर हैं, वे बड़े जिलों में 'स्वतंत्र कप्तान' (SSP) के रूप में काम कर रहे हैं। उनके लिए किसी कमिश्नर के नीचे 'एडिशनल एसपी' जैसी कार्यप्रणाली वाले पद पर बैठना मानसिक रूप से किसी पदावनति से कम नहीं लग रहा है। यही कारण है कि इस पद के लिए प्रस्तावित नामों में उत्साह की कमी देखी जा रही है।

नवा रायपुर का 'निर्वासन' कमिश्नरी की रीढ़ पर चोट?

चर्चा है कि हाईटेक सिटी 'नवा रायपुर' को कमिश्नरी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। इसे रायपुर रेंज (ग्रामीण) का हिस्सा बनाने की तैयारी है। यदि ऐसा होता है, तो राजधानी की नई पुलिसिंग व्यवस्था केवल 'पुराने शहर' के तंग गलियों और ट्रैफिक तक सिमट कर रह जाएगी। अफसरों का मानना है कि बिना नवा रायपुर के, कमिश्नरेट की चमक फीकी पड़ जाएगी।

वक्त कम, चुनौतियां ज्यादा

कमिश्नरेट लागू होने में अब हफ्ते भर से भी कम का समय बचा है, लेकिन अधिसूचना का न आना यह दर्शाता है कि पर्दे के पीछे खींचतान जारी है। यदि रायपुर पुलिस कमिश्नर को पर्याप्त अधिकार नहीं मिलते, तो यह व्यवस्था केवल 'पुराने शराब को नई बोतल' में परोसने जैसी होगी। राजधानी को एक ऐसे नेतृत्व की दरकार है जो न केवल अपराध पर नकेल कसे, बल्कि प्रशासन के भीतर अपनी 'धमक' भी बरकरार रख सके। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री इस 'प्रतिष्ठा की लड़ाई' का समाधान कैसे निकालते हैं।

आईएएस बनाम आईपीएस: अधिकारों की 'सर्जरी'

अधिसूचना जारी होने में हो रही देरी का मुख्य कारण आईएएस और आईपीएस लॉबी के बीच छिड़ी 'कोल्ड वॉर' है। कलेक्टरों के पास मौजूद दंडाधिकारी (Magisterial) अधिकारों को पुलिस को सौंपने के मार्ग में आईएएस लॉबी ने कई प्रश्न खड़े किए हैं।

- **क्या मिलेगा?** चर्चा है कि धारा 144 लागू करने और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जैसे 16 अधिकार कमिश्नर को मिलेंगे।
- **क्या नहीं मिलेगा?** शस्त्र लाइसेंस और आबकारी से जुड़े मलाईदार अधिकार फिलहाल कलेक्टरों के पास ही रहने की संभावना है। इसी 'आधे-अधूरे' पावर शेयरिंग ने आईपीएस अधिकारियों के बीच संशय बढ़ा दिया है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27